भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3580
(10 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ीएमआरडीएफ योजना

3580. डॉ॰ जयंत कुमार रायः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति (पीएमआरडीएफ) योजना को लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देशभर में मौजूदा पीएमआरडीएफ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कहां पर स्थित हैं;
(ख) क्या सरकार ने अध्येतावृत्ति योजना के कार्य प्रदर्शन की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;
(ग) अध्येतावृत्ति योजना के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए; और
(घ) क्या सरकार का देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए अध्येतावृत्ति योजना जारी रखने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) यह मंत्रालय वर्ष 2012 से राज्य सरकारों की सहभागिता में प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति (पीएमआरडीएफ) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह अध्येतावृत्ति देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में सेवा करने और सीखने हेतु युवा पेशेवरों के लिए एक लघु अवधि का कार्य-अवसर है। मंत्रालय ने दो बैचों में फेलो की भर्ती की थी। वर्ष 2012 में पहले बैच में 156 फेलों की भर्ती की गई थी और वर्ष 2014 में दूसरे बैच में 160 फेलो की भर्ती की गई थी। पहले बैच ने वर्ष

2016 में और दूसरे बैच ने वर्ष 2017 में अध्येतावृत्ति पूर्ण की थी। वर्तमान में किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई फेलो तैनात नहीं है।

(ख) से (घ): वर्ष 2013-14 में यूनीसेफ की सहायता से प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति (पीएमआरडीएफ) योजना की एक द्रुत समीक्षा की गई थी और अंतिम रिपोर्ट फरवरी, 2014 में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति (पीएमआरडीएफ) के निष्पादन के बारे में एक मिली-जुली तस्वीर प्रस्तुत की गई है और योजना की कमियों को दूर करके इसमें सुधार लाने की सिफारिशें की गई हैं। इस योजना की द्रुत समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर मंत्रालय द्वारा इस योजना में कुछ आशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

*****